

# न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या  
15/214/2023

रजि० नम्बर  
2023/672

प्रवेश तिथि  
03.10.2023

निर्णय दिनांक  
26.05.2025

1. राजेन्द्र पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बगडमेव तहसील रामगढ जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

## बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर।
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कार्यान्वयन ईकाई सोहना (हरियाणा)

—असल अप्रार्थीगण

3. ओम प्रकाश पुत्र विरेन्द्र
4. कमलेश पुत्री विरेन्द्र
5. गौरीशंकर पुत्र ज्वाला प्रसाद
6. जितेन्द्र पुत्र ज्वाला प्रसाद
7. त्रिवेन्द्र पुत्र ज्वाला प्रसाद
8. नरेन्द्र पुत्र ज्वाला प्रसाद
9. नवीन कुमार पुत्र विरेन्द्र
10. माया पालीवाल पत्नि स्व० विरेन्द्र
11. शलेन्द्र पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद
12. राधेश्याम पुत्र श्री विरेन्द्र, जातियान ब्राह्मण, निवासीयान ग्राम बगडमेव तहसील रामगढ जिला अलवर राज०

—तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित:—

01. श्री सनत कुमार जैन
02. श्री मोहनसिंह चौधरी एवं विजय नित्तल

—वकील प्रार्थी

—वकील अप्रार्थी 02



प्रार्थी ने यह प्रार्थना सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 3जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत पुनः मूल्य निर्धारण किये जाने बाबत पेश किया है। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जवाब प्राप्त किया गया। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई तथा वकील उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर  
अलवर (राज०)

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य की जिला अलवर में एन. एच. 148-एन के निर्माण (चौड़ा करने/चार लाईन का बनाने आदि) अनुरक्षण प्रबन्ध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए भारतीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई तथा जिन्हे समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया गया। तत्पश्चात् आक्षेपों का निस्तारण कर अधिनियम की धारा 3-घ के अनुसार भूमि को केन्द्र सरकार में निहित हो जाने की घोषणा की गई। उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण व अवाप्ति कार्यवाही के लिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अधिकृत विभाग हैं तथा प्रस्तावित योजना में अवाप्त भूमि का मूल्यांकन प्रचलित बाजार दर के आधुनिक गार पर नियमानुसार मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित है एवं मुआवजे का मूल्यांकन नियमानुसार विशेषज्ञों से कराया जाना विधि के अनुरूप है।

प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 10 रकबा 0.58 है 0, 118 रकबा 0.04 है 0, 119 रकबा 0.43 है 0, 12 रकबा 0.05 है 0, 8 रकबा 1.08 है 0 ग्राम बगडमेव तहसील रामगढ जिला अलवर की अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत की गई है तथा उक्त अधिनियम के तहत जो अवाप्ति की कार्यवाही की जाती है वह भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 105 के तहत चतुर्थ शेड्यूल में यह प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अवाप्त भूमि का मुआवजा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित किया जायेगा एवं इस बाबत केन्द्र सरकार द्वारा एक अध्यादेश भी दिनांक 31.12.2014 को पारित किया गया है कि उक्त मुआवजा सम्यन्धी प्रावधान दिनांक 01 जनवरी 2015 से लागू किए जायेंगे। इस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 जी (7) में जो मुआवजा तय करने का प्रावधान है, वे ऑवर राईड हो चुके हैं तथा उक्त मुआवजा के निर्धारण फेयर कम्पनरेशन्स एक्ट, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

फेयर कम्पनरेशन एण्ड ट्रांसपेरेन्सी इन लेण्ड एक्वजिशन एक्ट 2013 की धारा 26 में अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारित किए जाने की प्रक्रिया बतलाई है तथा धारा 29 में भूमि के ऊपर निर्मित परिसर, बोरिंग इत्यादि की कीमत का मूल्यांकन के प्रावधान के बारे में बताया गया है। उक्त प्रावधान के मुताबिक भवन परिसर बोरिंग इत्यादि का मूल्यांकन करने के लिए सक्षम इंजीनियर अथवा संबंधित विशेषज्ञ की सेवाएँ ली जायेंगी। मूल्यांकन के पश्चात् कुल मुआवजा राशि फेयर कम्पनरेशन एण्ड ट्रांसपेरेन्सी इन लेण्ड एक्वजिशन एक्ट 2013 के प्रावधानों के मुताबिक अवाप्तशुदा भूमि के निर्धारित मुआवजे पर 100 प्रतिशत सोलेशियम/तोषण दिये जाने का प्रावधान है तथा धारा 80 के मुताबिक प्रार्थी 9.1 व 15.1 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रार्थी की आराजी राजस्व अभिलेख में उनके नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा उनका कब्जा बहसियत खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। उक्त आराजी का सक्षम प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर राजस्थान द्वारा भूमि अर्जन, पुर्नवासन पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत घोषित किया गया है किन्तु अवाप्तशुदा आराजी से लगते हुए राजमार्ग के अनुसार जो डीएलसी रेट है, उस अनुसार तय नहीं किया गया है। जबकि नियमानुसार नेशनल हाईवे एवं स्टेट हाईवे से लगती हुई भूमियों का प्रचलित डीएलसी रेट से मुआवजा निर्धारित करते हुए मुआवजा दिया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त अवार्ड में भी अनेक कानूनी एवं तकनीकी खामियां की गई हैं तथा प्रार्थी की अवाप्तशुदा आराजी का भी मूल्यांकन सही प्रकार से नहीं करके विधिक प्रावधानों के विपरीत मूल्यांकन किया गया है तथा उसमें भी हल्का पटवारी द्वारा गलत प्रकार से रिपोर्ट बनाकर दी गई है, जो सभी कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 एवं अन्य राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा मौके की स्थिति एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत की गई है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित पूरक अधिनिर्णय/आदेश दिनांक 07-01-2023 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। जबकि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व ना तो

प्रार्थी को नोटिस दिया गया, न ही सुनवाई का तथा राक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर व मौका प्रदान किया गया। इस प्रकार राक्ष्य प्राधिकारी द्वारा भारी कानूनी त्रुटि की गई है।

प्रार्थी की भूमि स्टेट हाईवे से लगती हुई है जिसको भूमि अर्जन पुर्नवासन पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 एवं नेशनल हाईवे अधिनियम, 1956 के तहत अधिग्रहण किया गया है, जिस कारण उक्त अवार्ड में संशोधन करने का क्षेत्राधिकार माननीय आर्बीट्रेटर जिला कलक्टर अर्थात् न्यायालय श्रीमान को है। माननीय प्राधिकृत अधिकारी को तो उक्त 2013 के अधिनियम की धारा 33 के तहत लिपिकीय त्रुटि को ही दुरुस्त करने का अधिकार है, जिससे यह स्पष्ट है कि माननीय राक्ष्य प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा पारित संशोधित अधिनिर्णय क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर किए जाने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

भूमि अर्जन पुर्नवासन, पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 26 के अनुसार संपत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण अधिसूचना के जारी किए जाने के दिन को ही किया जाना चाहिये। जबकि राक्ष्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। यदि उनके द्वारा ऐसा किया जाता तो प्रार्थी को अपने अधिनिर्णय में पारित मुआवजा राशि पर 100 प्रतिशत सोलेसियम राशि के साथ ब्याज राशि भी दिलायी जाती। जिस कारण प्रार्थी की आराजी, जो स्टेट हाईवे से लगती हुई है, की प्रचलित डीएलसी रेट के अनुसार मुआवजा का निर्धारण होना चाहिये किन्तु ऐसा नहीं किया गया है जिससे भी उक्त अवार्ड निरस्त किए जाने योग्य है।

अप्रार्थीगण ने जो प्रारम्भिक आपत्ति जवाब के साथ प्रस्तुत की है, जो गलत एवं निराधार है। क्योंकि नियमानुसार एवं विधि के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे का निर्धारण नहीं किया गया है। क्योंकि भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के बाजार मूल्य पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोशण (Solatium) एवं REFTLARR Act, 2013 के प्रावधानानुसार धारा 3-ए के समाचार पत्र में प्रकाशन की दिनांक से अधिनिर्णय की दिनांक तक अतिरिक्त राशि तय करते हुए मुआवजा राशि का निर्धारण नहीं किया गया है, इसलिए मुआवजा निर्धारण विधि के प्रावधानों के अनुसार सही व उचित नहीं है।

आवेदक प्रार्थी की मौजूदगी में तहसीलदार साहब द्वारा प्रार्थी को मौका देखा गया न कोई जांच की गई है बल्कि कुल कार्यवाही प्रार्थी की गैरमौजूदगी में की गई है। भविष्य की संभावनाओं को देखा जाना आवश्यक है और उसी अनुसार मुआवजे का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। प्रार्थी अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जवाब में यह गलत अंकित किया गया है कि राक्ष्य प्राधिकारी द्वारा निकटतम नगर पालिका रामगढ से दूरी 4 कि. मी. मानते हुए 0 कि.मी. से अधिक व 10 कि.मी. तक के लिए 1.25 का गुणक लगाया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वांछित अनुतोष प्रदान किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को उसकी खातेदारी की अवातप्तशुदा आराजी में बॉरिंग व पेडपौधे आदि सहित का उचित दर से मुआवजा भूमि अर्जन पुर्नवासन, पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के वर्णित प्रावधानों के तहत दिलाया जावे एवं अप्रार्थी सं० 1 द्वारा पारित अधिनिर्णय दिनांक 07-01-2023 को निरस्त फरमाया जावे तथा पुनः संशोधित अधिनिर्णय/अवार्ड पारित किए जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से लिखित जवाब/बहस इस प्रकार है—?

1. कोई उत्तर अपेक्षित नहीं है।
2. कोई उत्तर अपेक्षित नहीं है।
3. कोई उत्तर अपेक्षित नहीं है।
4. कोई उत्तर अपेक्षित नहीं है।
5. हितवद्ध व्यक्तियों को अवाप्त की गई भूमि का प्रतिकर राशि का निर्धारण करते समय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3G(7)(A) के अनुसार ऐसी अवाप्ति हेतु धारा 3(A) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि को भूमि के बाजार मूल्य

के दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। उप पंजीयक, रामगढ के पत्रांक 561 दिनांक 30.09.2022 से प्राप्त डीएलसी की सूचना में उक्त अवाप्त भूमि आराजी खसरा नं. 10, 118, 119, 12 एवं 08 का राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्यमार्ग पर स्थित खसरों की सूची में अंकन नहीं हैं। खसरा नं. 265 अवाप्ति में नहीं है। इस बिन्दु के शेष तथ्य वादी के द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

6. कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, कथन सही नहीं है।
7. कथन सही नहीं है, भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्णतया पारदर्शी प्रक्रिया से की जाती है एवं अवाप्ति का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3A एवं 3D का प्रकाशन तत्समय भारत के राजपत्र में किया जाकर 02 समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन किया गया था।
8. कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, माननीय ऑबिट्रेटर से संबंधित है।
9. कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, माननीय ऑबिट्रेटर से संबंधित है।
10. बिन्दु सं. 05 के अनुसार यथावत एवं कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, माननीय ऑबिट्रेटर से संबंधित है।
11. कोई उत्तर अपेक्षित नहीं है।
12. कोई उत्तर अपेक्षित नहीं है।
13. कोई उत्तर अपेक्षित नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से लिखित बहस निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहतगठित एक संविधिक निकाय है जिसको कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, प्रबन्ध एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा प्राधिकरण का यह सत्त प्रयास है कि वह जन साधारण को सुरक्षित तथा पर्याप्त रूप से निर्मित व विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध कराये। भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोकहित को देखते हुए राजस्थान राज्य में नवप्रस्तावित राजमार्ग संरेखण (जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148-बी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के ग्राम पनियाला, जिला जयपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली-बडोदरा एक्सप्रेसवे (एन.एच.-148एन) के राज्यमार्ग 14 के जंक्शन गांव सीतल जिला अलवर तक निर्माण (चौडीकरण/पेड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध, प्रचालन करने के लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिए केन्द्रीय सरकार के सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3900 (अ) दिनांक 21.09.2021 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया।

यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य में नवप्रस्तावित राजमार्ग संरेखण (जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148-बी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के ग्राम पनियाला, जिला जयपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली-बडोदरा एक्सप्रेसवे (एनएच-148एन) के राज्यमार्ग-14 के जंक्शन गांव सीतल जिला अलवर तक), पनियाला-अलवर-बरोदामेव राष्ट्रीय राजमार्ग (इंटर कॉरिडोर रूट), के निर्माण (चौडीकरण/पेड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध, प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, जो कि राजस्थान राज्य के अलवर जिले में कि.मी. 3.150 से कि.मी. 86.513 तक के लिए अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा -3A की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा अधिसूचना संख्या का. आ. 4162(अ) दिनांक 08.10.2021 को जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 08.10.2021 को प्रकाशित की गयी। जिसका प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका में दिनांक 23.10.2021 को किया गया एवं अधिसूचना संख्या

का.आ. 689(अ) दिनांक 15.02.2022 को जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 15.02.2022 को प्रकाशित की गयी। जिसका प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों इण्डियन एक्सप्रेस और राजस्थान पत्रिका में दिनांक 01.03.2022 को किया गया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया।

उक्त अधिनियम 1956 की धारा 3 C री के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 3ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरुद्ध उरा भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3 A के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियों राक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा राक्षम अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा-3 A की अधिसूचना का सार उक्त समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के उपरान्त ग्राम बगडमेव तहसील रामगढ जिला अलवर की अर्जित भूमि के हिबद्ध व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा-3 C के अन्तर्गत आपत्तियां प्रस्तुत की गयी, जिनकी राक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सुनवाई की जाकर आपत्तियों को अननुज्ञात (रिजेक्ट) किया गया। राजस्थान राज्य में नवप्रस्तावित राजमार्ग संरक्षण (जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148-बी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के ग्राम पनियाला, जिला जयपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली-बडोदरा एक्सप्रेसवे (एनएच-148एन) के राज्यमार्ग-14 के जंक्शन गांव सीतल जिला अलवर तक), पनियाला-अलवर-बरोदामेव राष्ट्रीय राजमार्ग (इंटर कॉरिडोर रूट), के निर्माण (चौडीकरण/पेड्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध, प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, जो कि राजस्थान राज्य के अलवर जिले में कि.मी. 3.150 से कि.मी. 86.513 तक के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में राक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा-3 C के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात् राक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा-3ड के अन्तर्गत अधिसूचना का.आ. 3920(अ) दिनांक 22.08.2022 को जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 22.08.2022 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 12.09.2022 के अंकों में प्रकाशित किया गया तथा उक्त नोटिफिकेशन के पश्चात् समस्त अधिग्रहित निम्न भूमि:-

क्रम संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	10	निजी	बारानी 2	0.006
10	118	निजी	बारानी 3	0.04
11	119	निजी	बारानी 3	0.381
12	12	निजी	बारानी 2	0.016
73	8	निजी	चाही-3	0.673

वाके ग्राम बगडमेव तहसील रामगढ जिला अलवर सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहत हो चुकी है। उक्त धारा-3 D (1) के अन्तर्गत घोषणा के प्रकाशन के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाती है जिसमें उपरोक्त भूमि भी सम्मिलित है तथा जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा (F) के अनुसार धारा धारा-3 D के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित भूमि पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि पर निर्माण, रख-रखाव अथवा उससे सम्बन्धित अन्य कोई कार्य करने हेतु प्रवेश कर सकता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (G) में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तय करने सम्बन्धित प्रावधान दिये गये हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 G की उपधारा-1 व 2 के अनुसार भूमि का मुआवजा निर्धारण से पूर्व धारा धारा-3 D की अधिसूचना की लोक सूचना (Public Notice) जो कि दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व इण्डियन एक्सप्रेस दोनों में दिनांक 12.09.2022 के अंकों में प्रकाशित की गयी। उक्त लोक सूचना (Public Notice) द्वारा सम्बन्धित सभी हितबद्ध व्यक्तियों से धारा-3 G (3) व (4) के अन्तर्गत

स्वयं या विधिक अधिवक्ता के माध्यम से दावे मांगे गये। जिसके अन्तर्गत ग्राम-वगडमेव की अर्जित भूमि से सम्बन्धित भू-स्वामियों द्वारा दावे प्रस्तुत किया गया। जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सुनवाई कर निरस्तारण किया जाकर अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध में अवाई पारित कर दिया गया तथा प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णय आदेश क्रमांक 51 दिनांक 07.01.2023 को पारीत कर दिया गया।

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (G) के तहत, उपरोक्त अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (G) में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की गौके की स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किरम, सडक सीमा के पास या दूर, उप पंजीयक से प्राप्त डीएलसी दर के आधार पर की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(H) (1) के तहत अवाई की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी को जमा करवा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारण, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 (RFCTLARR) के अन्तर्गत, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3-क की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखों की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय-पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डी.एल.सी. दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (G) के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(G) में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अर्जित भूमि के बाजार मूल्य पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोशण (Solatium) वृद्धि की जाकर नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि विक्रय-विलेखों की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय-पत्रों के औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डी.एल.सी. दर का संज्ञान लेते हुए अधिनिर्णय आदेश क्रमांक 51 दिनांक 07.01.2023 को निर्धारित की गई।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3 A. B. C. D. E. F. G. एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जाकर सम्बन्धित खातेदार/हितबद्ध व्यक्तियों को सुना जाकर रिकार्ड एवं मौका की जांच सम्बन्धित तहसीलदार से करवाई जाकर नियमानुसार भूमि अवाप्ति कार्यवाही करते हुए अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा-3जी-7 (1) में यह प्रावधान किया गया है कि अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर का निर्धारण धारा 3-A के प्रकाशन के दिनांक पर प्रचलित बाजार दर के आधार पर की जावेगी न कि भविष्य की सम्भावनाओं के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि रिकार्ड एवं मौका की जांच सम्बन्धित तहसीलदार से करवाई जाकर नियमानुसार धारा 3 A की दिनांक को प्रभावी चयनित बाजार दर के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। प्रार्थी कोई अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारण, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम, 2013 (RFCTLARR) के अन्तर्गत, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3-क की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखों की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय-पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डी.एल.सी. दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया। जो कि निम्नानुसार है:-

:- उप-पंजीयक, रामगढ से प्राप्त ग्रामवार डी.एल.सी. दर निम्नानुसार:- (उप पंजीयक, रामगढ, जिला-अलवर के पत्रांक 561 दिनांक 30.09.2022 से प्राप्त सूचना के अनुसार)

क सं	ग्राम का नाम	भूमि की विराम	अधिकतम दर के 50 प्रतिशत विद्यमान पत्रों की औसत दर रु. (प्रति है०)		डी.एल.सी. दर (प्रति हैक्टेयर) 2021-2022			
			रोड के निकट	रोड से दूर	रोड के निकट		रोड से दूर	
					सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित
1	बगड मेव	कृषि	45,88,322	41,30,699	44,34,264	37,08,477	41,28,480	33,63,705
			/-	/-	/-	/-	/-	/-
	अर्जित भूमि के मुआवजा निर्धारण हेतु चयनित दरें			कृषि	45,88,322	37,08,477	41,30,699	33,63,705
					/-	/-	/-	/-

उपरोक्तानुसार अर्जित भूमि के मुआवजा निर्धारण हेतु धारा 3 A की दिनांक की प्रभावी खसरा नम्बर 10, खसरा नम्बर 12 असिंचित भूमि की रोड से दूर की चयनित बाजार दर रूपये 33,63,705/- प्रति हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 118, खसरा नम्बर 119 असिंचित भूमि की रोड के निकट की चयनित बाजार दर रूपये 45,88,322/- प्रति हैक्टेयर के आधार पर अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। अवाप्तशुदा भूमि की रिकार्ड एवं मौका की जांच सम्बन्धित तहसीलदार से करवाई जाकर नियमानुसार भूमि अवाप्ति कार्यवाही करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-26 की उपधारा-2 के अनुसार बाजार मूल्य पर गुणांक कारक के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के राजस्व (गुप-6) विभाग की अधिसूचना सं० प.1 (3) राज.6/2011/पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 (2013 का केंद्रीय अधिनियम सं० 30) की धारा 26 की उपधारा (2) सपटित प्रथम अनुसूची द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं० प.1 (3) राज. 6/2011/पार्ट/13 दिनांक 16.10.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारण हेतु बाजार मूल्य को जिस गुणक से गुणा किया जाना है, वह निम्न अनुसार होगा:-

शहरी क्षेत्र से दूरी	गुणक जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावे
0-10 कि.मी तक	1.25
10 कि.मी. से अधिक व 20 कि.मी. तक	1.50
20 कि.मी. से अधिक व 30 कि.मी. तक	1.75
30 कि.मी. से अधिक	2.00

उपरोक्तानुसार ग्रामों की अधिनिर्णित भूमि के लिये गुणांक निम्न प्रकार निर्धारित की गयी:-

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	निकटतम नगरपालिका	निकटतम नगरपालिका से दूरी (कि.मी.)	लागू गुणांक
अलवर	रामगढ	बगडमेव	रामगढ	4	1.25

इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निकटतम नगरपालिका रामगढ से दूरी (कि.मी.) 4 किलोमीटर मानते हुए 0 कि.मी. से अधिक व 10 कि.मी. तक के लिए 1.25 का गुणक लगाया

लगाया गया है। इस प्रकार राक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध जो गुणक निर्धारित किया गया है एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अर्जित भूमि के बाजार मूल्य पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोषण (Solatium), एवं RECTARR Act, 2013 के प्रावधानानुसार धारा 3A के समाचार पत्र में प्रकाशन की दिनांक से अधिनिर्णय की दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से अतिरिक्त राशि दी जाकर नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया। प्रार्थी कोई अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

राक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3A, B, C, D, E, F, G एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जाकर खातेदार/हितबद्ध व्यक्तियों को सुना जाकर रिकॉर्ड एवं मौका की जांच सम्बन्धित तहसीलदार से करवाई जाकर नियमानुसार भूमि अवाप्ति कार्यवाही करते हुए अवाप्ताधीन भूमि का अवार्ड पारित किया गया। प्रार्थी कोई अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। यदि किराी व्यक्ति ने कृषि भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ कर रखा था तो उनको विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत मुआवजे की दर कृषि भूमि की दर के हिसाब से ही दी गई है जो कि पूर्णतः सही व उचित है। अवाप्तशुदा भूमि की जो किस्म एवं खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी उसी के अनुरूप मुआवजा निर्धारित किया गया है। यदि अवाप्त शुदा भूमि को बिना विधिवत रूपान्तरित करवाये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज उसकी प्रकृति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग में लिया जा रहा है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार हैं तथा ऐसे अवैधानिक उपयोग के आधार पर मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोकहित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहित की गयी है। अधिग्रहण का उद्देश्य न तो आवासीय और न ही व्यावसायिक है। लोकहित में राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है जिसमें अधिक दूरी को कम समय में तय किया जा सके। ईंधन/उर्जा की कम खपत हो तथा मार्ग दुर्घटनाओं से बचा जा सके तथा आवागमन सुगम एवं सुरक्षित हो तथा अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित किया गया है जो विधि सम्मत एवं उचित है। वर्तमान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत की गई है।

अतः अप्रार्थी की ओर लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाने की कृपा करें। प्रार्थी किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया व वकील उभयपक्ष की लिखित बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार भूमि अवाप्ति प्राम बगडमेव तहसील रामगढ जिला अलवर के आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 0.58 है० (किस्म बारानी 2 असिंचित रोड से दूर), 118 रकबा 0.04 है० (किस्म बारानी 3 असिंचित रोड के निकट), 119 रकबा 0.43 है० (किस्म बारानी 3 असिंचित रोड के निकट), 12 रकबा 0.05 है० (किस्म बारानी 2 असिंचित रोड से दूर), 8 रकबा 1.08 है० (किस्म बारानी 3 सिंचित रोड के निकट) राष्ट्रीय राजमार्ग 148-एन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के ग्राम पनियाला जिला जयपुर से प्रारम्भ होकर दिल्ली-बड़ोदरा एक्सप्रेस-वे में अवाप्त की गई। अवाप्ताधीन भूमि एनएच एक्ट 1956 की धारा 3ए के तहत प्रकाशन दिनांक 08.10.2021 को किया गया एवं 3डी अधिसूचना संख्या 3920(अ) दिनांक 22.08.2022 को प्रकाशन की गई। राक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुख्य सड़क से दूर एवं भूमि की किस्म सिंचित डीएलसी दर गुणांक के आधार पर मुआवजा राशि मय सोलेसियम व ब्याज का अवार्ड पारित किया गया। प्रार्थीगण उक्त मुआवजा राशि से सन्तुष्ट नहीं होने पर पुनः मूल्य निर्धारण करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थीगण ने

प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनानुसार प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 0.58 है0, 118 रकबा 0.04 है0, 119 रकबा 0.43 है0, 12 रकबा 0.05 है0, 8 रकबा 1.08 है0 भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा फेयर कम्पनरेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लैण्ड एक्यूजिशन एक्ट 2013 की धारा 26 में अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारित किये जाने की प्रक्रिया दी गई है तथा धारा 29 में भूमि के ऊपर निर्मित परिसर, बोरिंग इत्यादि की कीमत का मूल्यांकन सक्षम इंजीनियर अथवा संबंधित विशेषज्ञ से नहीं कराया गया है साथ ही, धारा 80 के मुताबिक प्रार्थी 91 व 151 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी है। अवाप्तशुदा आराजी नेशनल हाई-वे एवं स्टेट हाई-वे से लगती हुई भूमि की प्रचलित डीएलसी रेट से मुआवजा निर्धारित किया जाना अपेक्षित था। उपरोक्त अवार्ड में अनेक कानूनी एवं तकनीकी खामिया की गई है तथा प्रार्थी की अवाप्त शुदा आराजी का मूल्यांकन भी सही प्रकार से नहीं करके विधिक प्रावधानों के विपरित मूल्यांकन किया गया है उसमें भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट द्वारा गलत प्रकार से रिपोर्ट बनाकर दी गई है। जबकि सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 3ए की जारी दिनांक से प्रचलित दर एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 0.58 है0 (किस्म बारानी 2 असिंचित रोड से दूर), 118 रकबा 0.04 है0 (किस्म बारानी 3 असिंचित रोड के निकट), 119 रकबा 0.43 है0 (किस्म बारानी 3 असिंचित रोड के निकट), 12 रकबा 0.05 है0 (किस्म बारानी 2 असिंचित रोड से दूर), 8 रकबा 1.08 है0 (किस्म बारानी 3 सिंचित रोड के निकट) का अवॉर्ड पारित किया गया है। उपपंजीयक रामगढ़ की प्राप्त प्रचलित डीएलसी दर में एनएच/एसएच में उक्त आराजी खसरा नम्बर अंकित नहीं होने पर गणना नहीं की गई। इसके कारण एनएच/एसएच की प्रचलित डीएलसी दर के अनुसार मुआवजा देय नहीं है। सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्त अधिकारी द्वारा तत्समय धारा 3ए के प्रकाशन दिनांक पर प्रचलित बाजार की डीएलसी दर के अनुसार प्रति हैक्टयर एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा निर्धारित कर सोलेसियम 100 प्रतिशत एवं RFCTLARR ACT 2013 की धारा 69 के तहत बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत ब्याज दिया जाकर दिनांक 07.01.2023 को अवॉर्ड पारित किया गया। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) द्वारा अवाप्त शुदा भूमि एवं अर्जित भूमि पर स्थित भवनों, वृक्षों आदि परिसम्पत्ति की मुआवजा राशि के सम्बन्ध में जो अवॉर्ड रिकॉर्ड एवं मौके की जाँच सम्बन्धित तहसीलदार से करवाई जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3A,B,C,D,D,F,G एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया है यह विधि के प्रावधानों के अनुसार सम्पूर्ण रिकॉर्ड एवं तथ्यों के आधार पर पूर्णतया सही पारित किया गया है। उक्त पारित अवॉर्ड में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आर्बिट्रेशन सार हीन होने पर खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 3जी(5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के तहत पुनः मूल्य निर्धारण किये जाने बाबत खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. आर्तिका शुक्ला)  
जिला कलेक्टर,  
अलवर राजस्थान